भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *236
दिनांक 09.07.2019/18 आषाढ़, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

चक्रवातों का पूर्वानुमान

*236. श्री गोपाल जी॰ ठाकुरः
श्रीमती रमा देवीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या चक्रवात आने की घटना की संख्या बढ़ रही है और सरकार चक्रवातों के संबंध में सही पूर्वानुमान लगाने में असमर्थ है;
(ख) क्या चक्रवातों से जान और माल की भारी क्षति होती है;
(ग) क्या सरकार का देश के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवातों के जोखिम को कम करने के लिए परियोजनाएं कार्यान्वित करने का विचार है जिससे कि ऐसे क्षेत्रों में रह रहे लोगों के कष्टों को दूर किया जा सके; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 09.07.2019 का लो.स.ता. प्र.सं. *236

'चक्रवातों का पूर्वानुमान' के बारे में दिनांक 09.07.2019 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *236 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): वर्ष 1891 से 2017 तक के आंकड़ों के अनुसार, उत्तरी हिन्द महासागर (एनआईओ) के ऊपर एक वर्ष में औसतन 5 चक्रवात पैदा होते हैं। हाल के वर्षों के दौरान चक्रवात की घटनाओं के बढ़ने का ऐसा कोई रूझान नहीं दिख रहा है।

चक्रवातों का पूर्वानुमान भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) द्वारा लगाया जाता है। आईएमडी ने चक्रवात के संबंध में पूर्व चेतावनी देने के लिए उपयुक्त तंत्र और प्रौद्योगिकी विकसित की है। आईएमडी के पास भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों को पार करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और देश भर में इसके कारण प्रतिकूल मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए हाई रिज़ॉल्यूशन युक्त विकसित गणितीय मॉडल के उपयोग वाली एक सर्वोत्तम पूर्वानुमान प्रणाली मौजूद है।

आईएमडी की चक्रवात पूर्वानुमान की सटीकता में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है जो कि फेलिन, हुदहुद, वरदा, तितली और फोनी चक्रवातों के दौरान प्रदर्शित हुआ है।

(ख): चक्रवात से होने वाली हानियां इसकी तीव्रता, साथ चलने वाली विनाशकारी हवा, तूफ़ान के झोंके और मूसलाधार वर्षा इत्यादि पर निर्भर करती है। तथापि, बेहतर पूर्वानुमान, बेहतर तैयारी और शमनकारी उपायों की वजह से चक्रवातों से होने वाली जन हानि में काफी कमी आई है।

(ग) और (घ): तटीय समुदायों, जो कि आमतौर पर गरीब हैं और विभिन्न प्रकार की आपदाओं की आशंका से घिरे रहते हैं, की पीड़ाओं को कम करने के लिए केंद्र सरकार 4903 करोड़ रूपये के कुल परिव्यय के साथ 8 तटीय राज्यों में "राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एनसीआरएमपी)" को कार्यान्वित कर रही है। इस परियोजना के तहत बनाये गये चक्रवात आश्रय स्थल और पूर्व चेतावनी प्रणाली वर्ष 2013 में 'फेलिन", वर्ष 2014 में "हुद-हुद", वर्ष 2018 में "तितली" और हाल में ही "फोनी" चक्रवात के दौरान काफी मददगार साबित हुई है।

****